

निदेशकों की रिपोर्ट

1. आर्थिक पृष्ठभूमि और बैंकिंग पर्यावरण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक विकास को 2020 में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, कोविड-19 महामारी से जीवन और आजीविका दोनों का काफी नुकसान हुआ है। 2019 में 2.8% की वृद्धि के मुकाबले 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.3% की दर पर संकुचित रहने का अनुमान है। लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण पहली छमाही में गंभीर नुकसान के बाद प्रतिबंधों को हटाने और दबी हुई मांग को उन्मुक्त करने के कारण, आर्थिक गति विधियां वर्ष के उत्तरार्ध में बढ़ती हुईं दिखाई। सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए त्वरित उपायों से भी वैश्विक मंदी को बहुत गंभीर होने से रोका जा सका। हालांकि, ऋण स्थिरता के बारे में चिंताएं उभरने लगी हैं क्योंकि कमजोर वर्ग की रक्षा और अर्थव्यवस्थाओं पर दीर्घकालिक नुकसान को सीमित करने के लिए देशों ने ज्यादा खर्च करना आरंभ कर दिया है। बाजार की उम्मीदों में परिवर्तन से बाहरी कर्ज के उच्चतर स्तर वाले देशों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

इस बीच, वैज्ञानिक समुदाय के जोरदार प्रयासों से विश्व स्तर पर कई टीकों को उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इससे इस संकट से बाहर निकलने की उम्मीद जगी है। लेकिन विश्व स्तर पर टीकों का असमान वितरण चिंता का विषय है। इसके अलावा, नए वायरस उत्परिवर्तन और बढ़ते संचरण अन्य कारक हैं जो वैश्विक विकास की संभावनाओं को धीमा कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में आईएमएफ ने 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था की 6% वृद्धि पर स्मार्ट रिकवरी का अनुमान लगाया है। यदि टीकों के उत्पादन और वितरण में तेजी आती है, दुनिया भर में बेहतर समन्वय किया जाता है और टीकाकरण की दर वायरस म्यूटेशन से आगे अधिक होती है, तो विकास के दृष्टिकोण में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न लागू प्रतिबंधों को जल्दी शिथिल करने और आर्थिक सुधार में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, आर्थिक दृष्टिकोण न केवल संक्रमण के लिए इंजेक्शन अनुपात पर ही, बल्कि इस संकट की वजह से हुए नुकसान को सीमित करने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करता है।

इसके साथ महामारी ने दुनिया को सीखने के लिए कई सबक भी दिए हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों को भी गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा था। प्रौद्योगिकी को त्वरित रूप से अपनाना और विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और स्वचालन पर ध्यान केंद्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

डिजिटल बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और पहुंच ने आर्थिक सुधार की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक अन्य क्षेत्र है जिसपर भविष्य में सभी राष्ट्रों को ध्यान केंद्रित करना होगा।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2021 स्वतंत्र भारत के पिछले 75 वर्षों के इतिहास में सबसे अशांत वर्ष था, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर कहर बरपाया। 2020 के अप्रैल-मई में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तथा तत्पश्चात इसके बाद के प्रभावों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% संकुचित हुई (वित्त वर्ष 2020 में 4.0% वृद्धि और वित्त वर्ष 2019 में 6.5% वृद्धि की तुलना में)।

विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र जीवित वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में संकुचन से बाहर हो गया और पूरे वित्त वर्ष के लिए वित्त वर्ष 2020 में 1.2% के संकुचन की तुलना में इसमें 7.0% की गिरावट हुई।

सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के चरणबद्ध लॉकडाउन खोलने के साथ वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में संकुचन से बाहर कदम रखा लेकिन वित्त वर्ष 2020 में 7.2% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में इसमें अभी भी 8.4% की गिरावट आई। कुछ गतिशीलता प्राप्त करने के बावजूद, संपर्क-रोकने सेवा क्षेत्र को कोविड-पूर्व स्तर तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।

इस तरह के विषादपूर्ण वर्ष में केवल कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि ही उम्मीद की किरण रही। वित्त वर्ष 2021 में खाद-बीज आदि तक पर्याप्त पहुंच, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून की पूरे देश में अच्छी बारिश, पर्याप्त जलाशय का स्तर और मिट्टी की नमी में सुधार के कारण कृषि जीवित वित्त वर्ष 2021 में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020-21 के लिए फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 305.44 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.7% अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन ने लगातार पांचवें साल एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

वित्त वर्ष 2021 में, लागत-वृद्धि के झटकों, आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों, मौसम के प्रभाव, कच्चे तेल की उच्च दरों और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों और उच्च करों की एक श्रृंखला के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति ने लॉकडाउन और लॉकडाउन पश्चात अवधि (अप्रैल-नवंबर 2020) में लगातार आठ महीनों के 6% की ऊपरी सहय सीमा को पार कर गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव व्यापार और परिवहन लागत, टैक्स और ऑटो किराए में

दिखाई दे रहा है और इसके दूसरे दौर के प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को व्यापक आधार पर बढ़ा सकते हैं। इसके कारण, वित्त वर्ष 2021 के लिए वार्षिक औसत सीपीआई मुद्रास्फीति 6.2% थी, जबकि वित्त वर्ष 2020 में 4.8% थी।

वित्त वर्ष 2021 के दौरान माल निर्यात और आयात में संकुचन विश्व व्यापार और वैश्विक मांग की नाजुक स्थिति का संकेतक है। वित्त वर्ष 2020 में 5.1% की गिरावट की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में भारत के माल निर्यात (वर्षानुवर्ष) में 7.3% की गिरावट आई, जबकि वित्त वर्ष 2020 में आयात में 7.7% के संकुचन की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में आयात में 18.0% की भारी गिरावट आई है। निर्यात की तुलना में आयात में बड़ी गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2021 के अप्रैल-दिसंबर में चालू खाते में सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% अधिशेष हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2020 के अप्रैल-दिसंबर में 1.2% का घाटा था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्रामीण मांग में वृद्धि, शहरी मांग के मजबूत होने, निवेश की मजबूत मांग और निर्यात के कारण वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत पूंजीगत व्यय के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ-साथ आत्मनिर्भर 2.0 और 3.0 के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन से निश्चित रूप से सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश में तेजी आएगी। हालांकि, संक्रमण में वृद्धि, नए म्यूटेंट, आंशिक लॉकडाउन, गैर-तेल वस्तुओं की उच्च कीमतें और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता विकास के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

मुद्रास्फीति के प्रति दृष्टिकोण अनेक कारकों पर निर्भर करेगा। जहां सुस्त आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों, वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और इनपुट लागत में मजबूत दखल के माध्यम से शीर्षक मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, वहीं प्रत्याशित से कम वैश्विक मांग, भरपूर खाद्यान्न उत्पादन और प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है। शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि भारत में इस साल (लगातार तीसरी बार) मानसून सामान्य रहेगा।

सेवाओं के जबरदस्त निर्यात और धन प्रेषण में वृद्धि के साथ, भारत में वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता अधिशेष होने की उम्मीद है। अमेरिकी रिकवरी को मजबूत करने से होने वाले पूंजी बहिर्गमन के कारण रुपये में अवमूल्यन का दबाव देखने की आशंका है। हालांकि, बाहरी क्षेत्र के मैट्रिक्स अनुकूल बने हुए हैं क्योंकि आरबीआई के पास मुद्रा की रक्षा के लिए



एसबीआई श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश में एसबीआई योनो लोकार्पित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में 18 मार्च 21 को इसे वर्चुअल रूप से लोकार्पित किया गया।

पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे अनुमानित दुष्प्रभाव देखने की उम्मीद नहीं है क्योंकि कमजोरी केवल चालू खाते के घाटे और कम पूंजी प्रवाह से उपजी है।

बैंकिंग पर्यावरण

बैंकिंग क्षेत्र के वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में ऋण की मांग कम रही। हालांकि, दूसरी छमाही में ऋण उठाव में सुधार हुआ, जिसने अक्टूबर के प्रारंभ में ही गति पकड़ ली तथा नवंबर से (वित्तीय वर्ष आधार पर) वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020 में 6.1% की वृद्धि की तुलना में एससीबी क्रेडिट 5.6% के साथ 59 साल के निचले स्तर पर आ गया है। दूसरी ओर, जमा वृद्धि मजबूत रही और वित्त वर्ष 2021 में 11.4% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2020 में 7.9% की वृद्धि हुई, जो उच्च अनिश्चितता के चलते एहतियाती बचत को दर्शाती है। इसके अलावा, 'एससीबी के जमा और ऋण पर त्रैमासिक आंकड़े' पर आरबीआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रमशः 3.6% तथा 9.1% वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान विदेशी बैंकों द्वारा ऋण में कमी आई। वित्त वर्ष 2021 में एससीबी की ऋण वृद्धि में कमी विस्तृत आधार वाली है जो कृषि के अलावा अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त के हैं।

मार्च 2021 के लिए बैंक के ऋण के क्षेत्रगत आबंटन के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वृद्धि 12.3% दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 4.2%), जो अप्रैल 2017 के पश्चात सर्वाधिक है। प्रमुख रूप से बृहद उद्योगों को ऋण, जो मार्च 2021 में 0.8% संकुचित हुआ (एक वर्ष पहले 0.6% वृद्धि की तुलना में), के कारण उद्योग के लिए ऋण वृद्धि में 0.4% की हल्की गिरावट आई (एक वर्ष पहले 0.7%)। इसका प्रमुख कारण बृहद उद्योगों द्वारा गैर- बैंक स्त्रोतों से संसाधन प्राप्त करना है। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के 7.4% से गिरकर वित्तीय वर्ष 2021 में 1.4% रही, जो प्रमुख रूप से पिछले वर्ष उछाल के पश्चात एनबीएफसी में ऋण वृद्धि में तीव्र कमी तथा पेशेवर सेवाओं को ऋण में संकुचन के कारण है। आगे, बैंक के कुल ऋणों में वैयक्तिक ऋणों का एक चौथाई हिस्सा रहा तथा पिछले वर्ष की 15.0% वृद्धि की तुलना में 10.2% की दोहरे अंकों की वृद्धि दर जारी रखी, जिसमें आवास तथा अन्य वैयक्तिक ऋण अग्रणी रहे।

महामारी के दौरान बाजार और अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए, आरबीआई ने कई तरलता उपायों की घोषणा की और प्रमुख नीति रेपो दर को 115 बीपीएस से घटाकर 4.0% और सीआरआर 100 बीपीएस घटाकर 3.0% तक कर दिया। इस प्रकार, ब्याज दरों में कमी का

परिदृश्य, बृहद अधिशेष तरलता, बाहरी बेंचमार्क संबद्ध ऋण दरों तथा अधीनस्थ ऋण मांग के सहयोग से जमा और ऋण दरों में गिरावट के साथ जारी रहा है। अगर हम एससीबी को देखें तो वित्त वर्ष 2021 के दौरान ऋण दर (नए ऋण पर भारित औसत ऋण दर) में 79 बीपीएस (पीएसबी: 120 बीपीएस, प्राइवेट बैंक: 22 बीपीएस) और भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में 100 बीपीएस (पीएसबी: 89 बीपीएस, निजी बैंक: 101 बीपीएस) की कमी आई है।

वर्तमान महामारी ने भौतिक संपर्क के पूर्ण अभाव के समय में व्यापार निरंतरता बनाए रखने और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला है। मोबाइल बैंकिंग के लिए रुझान उत्साहजनक है। अप्रैल 2020 में रु. 3.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मोबाइल बैंकिंग भुगतान कोविड के भय से जनित लॉकडाउन के कारण जनवरी 2021 में 9.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कोविड के भय से लगे लॉकडाउन से प्रेरित है। इसी तरह यूपीआई लेनदेन अप्रैल 2020 में 1.5 लाख करोड़ से 145% की वृद्धि इंगित करते हुए बढ़कर मार्च 2021 में 5.0 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यूपीआई का तेजी से उदय चौबीसों घंटे उपलब्धता, विभिन्न बैंक खातों तक पहुंचने के लिए एक एप्लीकेशन, अधिक सुरक्षित वर्चुअल आईडी, जिसके लिए जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं है, के उपयोग, जैसी सुविधाओं



कवच

कोविड उपचार के लिए पर्सनल लोन

न्यूनतम ब्याज दर 8.50% प्र.व. की दर पर

#InThisTogether

प्रमुख विशेषताएं*

- ऋण राशि: अधिकतम ₹5 लाख
- 60 महीने तक की चुकोती (3 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित)
- कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आवश्यक

विवरण के लिए, विज़िट करें bank.sbi या कॉल करें 1800 11 2211 पर या अपनी शाखा में जाएं.



*विषय व शर्तें लागू

के कारण हुआ है। इससे पता चलता है कि भविष्य में भी बैंकों को अपने कारोबार के विस्तार और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए सुरक्षित तथा उपयोग में आसान डिजिटल एप्लीकेशन्स उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

दृष्टिकोण

पिछला वित्त वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के दर्ज इतिहास में सभी मानकों पर असाधारण था। वित्त वर्ष 2021 में वायरस फैलने और उसके बाद लगा लॉकडाउन बैंक के लिए परीक्षा की घड़ी थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद बैंक के बैंकिंग कामकाज लगातार जारी रहे।

फरवरी 2021 में प्रगतिशील रूप से खोले जाने तक वित्त वर्ष 2021 व्यावहारिक रूप से लॉकडाउन में रहा। इससे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। घरेलू मांग में अचानक हुए नुकसान का असर ऋण मांग पर पड़ा। अधिकांश वर्ष के लिए जमा वृद्धि, ऋण वृद्धि से अधिक रही, जो विवेकाधीन खपत में अचानक गिरावट को दर्शाती है। इससे जमा दरों पर लगातार दबाव पड़ा है, जिनमें गिरावट देखी गई।

महामारी ने आपूर्ति पक्ष की अप्रत्यक्ष मुद्रास्फीति प्रवृत्ति को भी उजागर किया है, जो अब मूल्य सूचकांकों में दिखाई देने लगी है। इसलिए मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक के कार्यवृत्त में इसे एक जोखिम के रूप में रेखांकित किया गया है जिसे निगरानी और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

कोविड-19 महामारी के अलावा, वित्त वर्ष 2021 को अन्य स्थानीय आपदाओं, जैसे कि उत्तरी राज्यों को प्रभावित करने वाला टिड्डी हमला, देश के पूर्वी हिस्से में बर्ड फ्लू और बाढ़ की प्रकोप से भी जूझना पड़ा।

वित्त वर्ष 2021 में 7.3% के संकुचन की तुलना में वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है (आरबीआई)। हालांकि, चालू वित्त वर्ष कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ शुरू हुआ है और विशेषज्ञों ने सूचित किया है कि भारत में वायरस स्टेन म्यूटेट हुआ है। तदनुसार, कामकाजी आबादी का त्वरित प्रतिरक्षण सबसे इष्टतम परिदृश्य होगा, जो विकास के दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। इस वित्तीय वर्ष में मांग कैसे बढ़ेगी, इस पर काफी अनिश्चितता है- विशेष रूप से यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि पूंजी निर्माण में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा या नहीं।

इस पृष्ठभूमि में बैंक के कारोबार का सावधानीपूर्वक आकलन करने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2021 में तैयार की गई व्यावसायिक निरंतरता योजनाओं ने अच्छी तरह से काम किया है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बैंक का सहयोग संतोषजनक रहा है। लेकिन दूसरी लहर के साथ, अधिक विस्तृत योजना की आवश्यकता होगी। बैंकों ने प्रदान किए गए बफर के अलावा हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए आकस्मिक बफर बनाए हैं। पहले से उपलब्ध हानियों के अलावा संभावित अप्रत्याशित हानियों के संदर्भ में दूसरी लहर के कारण बैंकों की

परिसंपत्ति गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एमएसएमई खंड में तनाव को दूर करने के लिए बैंक को हाल ही में अधिसूचित प्री-पैकेज इनसॉल्वेंसी मार्ग का सहारा लेना चाहिए।

हालांकि, जैसा कि पिछले साल उल्लेख किया गया है, कोविड-19 महामारी ने भी बैंकों के लिए अवसर खोले हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से व्यवस्थित करना भारत के लिए वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में खुद को स्थान देने का अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, एक प्रस्ताव जो अब भी उपलब्ध है। कोविड-19 की प्रतिक्रिया स्वरूप डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने से बैंक को पिछले वर्ष काफी लाभ हुआ है।

संक्षेप में, बैंक के कारोबार और अर्थव्यवस्था पर दृष्टिकोण उस समय सीमा तक के लिए सशर्त होगा जब वायरस पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा उल्लिखितानुसार एक अन्य राजकोषीय पैकेज के लिए गुंजारश में कमी आई है और संभावित राजस्व उत्पादन में 400 आधार अंकों की तेज गिरावट आई है। इस प्रकार, बैंक के लिए यह जरूरी है कि व्यापार प्रक्रियाएं नए परिचालन माहौल को अपनाती रहें।